के दौरान एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिसकी अध्यक्षता कुमारी अनीता ग्रोवर ने की थी तथा जिसके सदस्य सर्वश्री वी० कुमार डी० एन० भौमिक, आई० के० सूरी तथा एन० के० सदाशिवम थे । समिति ने 11.654 टन यूरिया कम पाया जिसका मुख्य कारण उत्पादन की घोषणा में नई गलतियां तथा सिलो में वास्तविक भंडार के आंकलन में अन्तर्ग्रस्त कठिनाई थी, विशेषतः जब सिलो में उच्च भंडार होता है । यह कमी अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1985/जनवरी 86 से संबद्ध थी ।

(ख) यूरिया संयंत्र में उत्पादन का निर्धारण बेल्ट वेयर की गणना के आधार पर किया जाता है । यद्यपि वह खराब नहीं था किन्तु उसका निष्पादन मुख्यतः यूरिया के उत्पादन की अस्थिर दर के कारण अशुद्ध में था । समिति ने पाया कि सुधारक उपायों को नियमित रूप से लागू नहीं किया गया, यद्यपि निर्देशों के अनुसार इसकी पन्द्रह दिनों में एक बार जांच गई । यूरिया को पैकेजिंग के लिए बैगिंग संयंत्र में तथा स्टोर में प्रयुक्त तुलन मशीनों में कोई दोष नहीं पाया गया । प्रेषित मात्रा भरी हुई बोरियों के रूप में ज्ञात होती थी । यह तथ्य नहीं है कि बोरियों को यूरिया की कमी के कारण बेचा गया। अतः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये किन्तु उनके नाम बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि वे दोषी हैं या नहीं । निदेशकों के बोर्ड ने दोषी पाये जाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया है।

बिहार में दरभंगा में नारियल के पौधे लगाने में अनियमितताएं

3168. **श्री अशोक नाथ धर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने अपने 24 मार्च, 1986 के पत्र द्वारा बिहार के दरभंगा जिले में नारियल के पौधे लगाने और उर्वरकों और बीज के वितरण में की गई गड़ बड़ी की जांच किए जाने की मांग की है ;

(ख) क्या इन आरोपों को सच पाया गया ; यदि हां, तो ब्लाक-वार कितने-कितने नारियल के पौधे वितरित किये गए, कितने पौधे खरीदे गए तथा कहां से वह किस कीमत पर खरीदे गए; उर्वरक और बीज की ब्लाक-वार कितनी-कितनी मात्रा वितरित की गई तथा उस अवधि के दौरान जिन किसानों को यह वितरण किया गया उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ग) क्या इस समय एक भी नारियल का पेड़ नहीं है, यदि हां, तो वे पेड़ कहां गए, और यदि नहीं, तो ब्लाक-वार शेष बचे पेड़ों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन सभी आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो या सी० आई० ए० द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Import of Fishing Trawlers

3169. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what is our last three years import of fishing trawlers, indicating the number and the amount spent thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI YOGENDRA MAKWANA): During the last three years 31 fishing trawlers have been imported and the amount spent is Rs. 2419 lakhs approximately.

Water to Madras City under the Telugu Ganga Project

3170. DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the propostal to give water to Madras city under the Telugu-Ganga Project has been finalised;

(b) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons for the delay in implementing the proposal; and

(c) by when the Telugu-Ganga project is likely to be completed?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) The Telugu-Ganga, Project *inter alia* envisages supply of water for Madras City. The proposal has not been finalised because the techno-economic clearance cannot be given until the inter-State issues are resolved and clearance from the environmental and forest conservation angles has been obtained by the State Government.

Potable Water to Villages

3171. DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of villages provided with potable water during the Sixth Five Year Plan;

(b) what was the target for the Sixth Plan; and

(c) what are the targets set up for the supply of potable water during Seventh Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) During the Sixth Plan 1,92,024 problem villlages were provided with drinking water facilities.

(b) During the Sixth Plan, the aim was to cover 2,30,784 problem villages.

(c) During the Seventh Plan, the target is to cover approx. 227000 problem villages.

Setting up of Soda Ash Plant at Phulpur

3172. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether in December, 1981 the then Minister of Agriculture had announced that a Soda ash plant would be set up by the Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited at Phulpur; and

(b) if so, the reasons for not setting up of the plant so far.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) We have no records to show that the then Minister of Agriculture had made such an announcement. However, IFFCO had been granted a letter of Intent in 1982 for setting up a Soda ash/ammonium chloride plant at Phulpur. The plant could not be set up mainly due to the folowing reasons:—

(i) The project envisaged utilisation of surplus ammonia and carbon dioxide from the existing amonia plant after meeting the full requirements of urea plant, but operation of the existing ammonia plant during the past four years has not yielded any surpluses;

(ii) The plant was to be based on indigenous technology, which has not stabilised at a high level of production;

(iii) The project cost has escalated by about Rs. 20 crores and might increase further if imported technology has to be used. This